Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Full Test) (Model Answer)

DATE : 29-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

1. भारत में विकास के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

Examine the role of international institutions with reference to development in India.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संक्षेप में बताएं।
- अगले पैरा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विकास में भूमिका स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

उत्तर- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन :** अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं, जिसके सदस्य, कार्यक्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। स्वरूप, आकृति एवं प्रयोजनों की दृष्टि से भिन्न होते हुए भी यह संगठन मानवीय हित में कार्य करता है। इसी प्रकार भारत के विकास में भी इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका से व्यापक रूप से प्रभावी रही है, जिसे निम्नलिखित तथ्यों से इसे समझा जा सकता है-

1. इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित देशों को अधिक व आसान शर्तों पर विकास साख उपलब्ध कराकर उनके वित्तीय व आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना है।
2. इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऐसोसिएशन, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने का कार्य करता है, साथ ही यह अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनेक कार्यों का सम्पादन समय-समय पर किया जाता है।
3. कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए धन या ऋण उपलब्ध कराते रहे हैं। जैसे- विश्व बैंक द्वारा भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, बाँध व नहर जैसी परियोजनाओं के निर्माण इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता रहा है।
4. देश की विकास संबंधी नीतियाँ अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका से प्रभावित होती रहीं हैं। जैसे- आर्थिक नीतियाँ, मानवाधिकार, पर्यावरण इत्यादि।

* * *

GS World Committed To Excellence

Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Full Test) (Model Answer)

DATE : 29-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

2. भारत में नीति निर्माण की समस्याओं की चर्चा करते हुए इसमें मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the problems of policy making in India, while explaining the role of media in this.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में नीति निर्माण के बारे में संक्षेप में बताएं।
- अगले पैरा में इसकी समस्याओं की चर्चा करें।
- फिर अगले पैरा में मीडिया की भूमिका स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

उत्तर- नीति निर्माण एक आवर्ती प्रक्रिया (Recurring) है। नीतियों का वास्तविक निर्माण विभिन्न राजनैतिक दलों के राजनेताओं, दबाव व हितबद्ध समूहों, नीति निर्माण इकाइयों तथा जनता द्वारा समग्र रूप से साझा किया जाता है। फिर भी सभी नीतियाँ मुद्दों का निराकरण करने की गंभीर प्रतिबद्धता नहीं दिखा सकती हैं। इसके मार्ग में भी कई प्रकार की बाधाएं विद्यमान होती हैं-

1. वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता एक समस्या है, जो नीतिगत प्रक्रिया की निर्बाध क्रियाशीलता को प्रभावित करती है।
2. लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव तथा अल्पावधि लाभ भी अवरोध के रूप में काम करते हैं। राजनैतिक हस्तक्षेप, जनता के समर्थन का अभाव, समाज के प्रबुद्ध वर्ग की गैर-सहभागिता कुछ अन्य अवरोधक हैं।

नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका काफी प्रभावित रही है एवं लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज पर नजर रखने के लिए मीडिया को 'चौथे स्तम्भ' के रूप में जाना जाता है। अनेक कार्यों में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है, मीडिया समय-समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। यह लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का साधन है एवं समाज के उपेक्षित विषयों के बारे में सरकार तक जानकारी पहुँचाना जिससे नीति निर्माण के संबंध में मीडिया सहायक की भूमिका निभाती है।

* * *

Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Full Test) (Model Answer)

DATE : 29-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

3. लोकतंत्र व सुशासन एक-दूसरे के पूरक हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

Democracy and good governance are complementary to each other. Examine this statement.
(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में लोकतंत्र व सुशासन के बारे में संक्षेप में बताएं।
- अगले पैरा में लोकतंत्र व सुशासन के संबंध को स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

उत्तर- लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है, जो नागरिकों को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की भागीदारी पर आधारित है, वहीं सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक-राजनैतिक इकाई को इस प्रकार चलाना है कि वह वांछित परिणाम दें।, जिससे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शासन की प्राप्ति हो सके। उदाहरण- कानून का शासन, प्रशासन में लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता इत्यादि।

लोकतंत्र एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में निहित होती है, वहीं अच्छा शासन एक कल्याणकारी एवं जनहितकारी व्यवस्था है। एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, अच्छा शासन सरकार की कुशल कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है, जो लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक दोनों व्यवस्थाओं में हो सकता है। विश्व बैंक ने भी अच्छे शासन की संकल्पना के प्रतिपादन में सत्ता के उद्देश्य व कार्यप्रणाली के परिवर्तन पर बल दिया है, वहीं अच्छा शासन अपनी शैली में उद्देश्यपरक एवं विकासोन्मुखी शासन के समान है, जो जनता के लिए सतत् सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी विकासशील देशों के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को अपने विश्लेषणकारी, सलाहकारी और वित्तीय प्रयासों में सम्मिलित किया गया है। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल देते हुए उत्तरदायित्व के निर्धारण के साथ लक्षित कार्यक्रमों के निर्माण की बात कही गई है, वहीं सुशासन की अवधारणा को इसीलिए नवीन लोकप्रबंधन से भी जोड़ा गया है, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन निष्पादन आधारित उत्तरदायित्व का पक्षधर है। इस प्रकार सुशासन सभ्य समाज की सरकार के साथ गठजोड़ को सहयोग और सहसंबंध के रूप में बढ़ावा देता है।

* * *

Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Full Test) (Model Answer)

DATE : 29-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

4. भारत में ई-गवर्नेंस प्रणाली की सफलता का मूल्यांकन करते हुए इसके समस्यात्मक पक्ष को भी विश्लेषित कीजिए।
(250 शब्द, 15 अंक)

Evaluate the success of e-governance system in India and also analyze its problematic aspect.
(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में ई-गवर्नेंस की परिभाषा को संक्षेप में बताएं।
- अगले पैरा में इसक सफलता का मूल्यांकन कीजिए।
- फिर अगले पैरा में इसकी समस्यात्मक पक्ष को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

उत्तर- शासन की गतिविधियों में सूचना एवं संचार साधनों का प्रयोग ई-शासन कहलाता है। सूचना एवं संचार का अर्थ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे- कम्प्यूटर, लैपटॉप, पेजर इत्यादि से है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला एवं प्रभावी कदम था, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को कानूनी वैधता प्रदान की गई। 2005 में गवर्नेंस की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को ई-जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार संघ सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरूआत की। जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी पर आधारित एक ज्ञानवान भारत की स्थापना करना है। यह ई-गवर्नेंस से संबंधित एक समंवित कार्यक्रम है। इस प्रकार ई-गवर्नेंस के पहलू निम्नलिखित हैं-

1. ब्रॉडबैंड हाइवेज का निर्माण
2. सभी के लिए इंटरनेट की उपलब्धता
3. सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा शासन में सुधार
4. सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक उपलब्धता, ई-क्रांति

समस्याएं-

1. आधारभूत संरचना का अभाव जैसे विद्युत आदि का अभाव।
2. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त अभाव।
3. प्रशासनिक सुधारों की धीमी गति।
4. प्रक्रियागत कमजोरी अर्थात विभागों की कार्य प्रणाली में अनेक दोषों की विद्यमानता।

* * *

GS World Committed To Excellence

Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Full Test) (Model Answer)

DATE : 29-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

5. सामाजिक लेखा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रशासन के संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

What do you mean by Social Audit? Discuss its importance with reference to administration.

(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में सामाजिक लेखा परीक्षण के बारे में संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
- अगले पैरा में प्रशासन के संदर्भ में इसके महत्व को बताएं।
- अंत में सुधारात्मक उपायों/सुझावों को बताते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- सोशल ऑडिट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 के दशक में हुआ था। इसका जन्मदाता थियोडोर जे. क्रिप्स को माना जाता है। भारत में 1993 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सोशल ऑडिट की शुरूआत की गई थी। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यो का सोशल ऑडिट करे अर्थात् सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियाँ अपने विकास कार्यो से सम्बन्धित ब्यौरे किसी सार्वजनिक मंच पर लोगों से साझा करती है। इससे जनता को न सिर्फ विकास कार्यो की जाँच का मौका मिलता है, बल्कि प्रशासन एवं विकास कार्यो में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

महत्व -

1. यह प्रशासन को पारदर्शी व जवाबदेह बनाता है।
2. यह लोगों को सरकारी नीतियों एवं उनके अधिकारों के विषय में जागरूक बनाता है।
3. इससे लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती है।
4. यह प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है।
5. जिन संस्थाओं पर कैग का ऑडिट संबंधी अधिकार अस्पष्ट है, उनके ऑडिट के लिए सोशल ऑडिट कारगर विधि है।
6. यह समुदायों के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनमें सुधार करने में प्रशासन की सहायता करती है।
7. सोशल ऑडिट योजनाओं की प्रकृति के भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध करवाता है।

* * *

Skill Development Programme

For Answer Writing

Governance (Full Test) (Model Answer)

DATE : 29-May-2018 **TIME : 11:45 am**

मुख्य परीक्षा

6. भारत के संदर्भ में 'लोक सेवा सक्रियतावाद' की व्याख्या कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

Describe 'Civil Services Activism' with reference to India.

(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में 'लोक सेवा सक्रियतावाद' के बारे में स्पष्ट कीजिए।
- अगले पैरा में लोक सेवा सक्रियतावाद की प्रशासन में सक्रिय भूमिका के बारे में बताएं।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

उत्तर- 'न्यायिक सक्रियता' की तरह आजकल 'लोकसेवा की सक्रियता' भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोक सेवा की सक्रियता की अवधारणा 'लोकसेवा की तटस्थता' से जुड़ी हुई है। एक लोकसेवक को तटस्थता व अनामता की अवधारणा को पूर्ण करते हुए सक्रियता की ओर उन्मुख होना चाहिए। भारत में इसके संदर्भ में सरकारी सेवक को राजनीतिक संगठन का सदस्य होने तथा किसी भी राजनीतिक आंदोलन या कार्य में भाग लेने या उसके लिए चन्दा देने या किसी भी प्रकार सहायता देने का निषेध किया है।

लोकतांत्रिक विधान व शासन में राज्य में कर्मचारी निर्दलीय व निरपेक्ष रहें, तभी शासन में दक्षता आ सकती है। दूसरा पहलू यह भी है नौकरशाह समाज के विवेकी अंग हैं और जैसे-जैसे शासन का कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। अतः उनको राजनीतिक क्रिया-कलापों से दूर रखने से समाज का एक बड़ा अंश राजनीति के लिए पंगु एवं निष्क्रिय हो जाता है। इसी प्रकार लोक सेवा का परम्परागत गुण तटस्थता रहा है, जिसमें निष्पक्षता भी शामिल है। लोक सेवक अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारों या धारणाओं से मुक्त रहता है। लोक सेवा तटस्थता संबंधी बिन्दु इस प्रकार है-

1. लोक सेवक को राजनीतिक पक्षपात मुक्त होना चाहिए, जिससे की वह प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा सके।
2. मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी दल सत्तारुढ़ हो, लोक सेवक की निष्ठा उन्हें प्राप्त रहेगी।
3. लोक सेवक नैतिक साहस का आधार विश्वास है कि पदोन्नति तथा अन्य पुरस्कार राजनीतिक दृष्टिकोण या पक्षपातपूर्ण कार्यों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि गुणों पर निर्भर करते हैं।

* * *